सं. यो. वि/पानी/41-84/26388.--चूंकि हरियाणा केराज्यपाल की राये है कि दी हरियाणा हैण्डलूम्ज बीवर्ज एपैक्स कोपरेटिव सोसायटी लि., पानीपत के श्रीमक श्री राम चन्द्र तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रंब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधित्यम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं. 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 19 ग्रप्रैल, 1984 द्वारा उक्त ग्रिधित्यम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय ग्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायिनण्य के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त है या विवाद से संसुगत ग्रथवा संबंधित मामला है।

क्या श्री राम चन्द्र की सेवाग्रों का समापन त्यायचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो बह किस राहत का हकदार है ?

सं मोटिव/सोनीपत/83-83/26395. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि जनरल मैनेजर मै. हरियाणा एग्रो फूड एण्ड फूट प्रोसेंसिंग प्लांट मुख्यल सोनीपत के श्रमिक सतीश चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है,

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ?

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उमधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-म्रो-(ई) अम-80/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय रोहतक को विवादाग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादाग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है,

क्या श्री सतीश चन्द की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित है, तथा ठीक है? तो वह किस राहत का हकदार है।

स॰ श्रोब॰ ी/यमुना/ 47-84/ 26402. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये हैं कि न्यू जनता मिल्ज खालसा कालज रोड, यमुनानगर के श्रमिक श्री राम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य रसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्ययोगिक विवाद है;

भौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं

इसलिए अब, औद्ययोगिक विवाद अधिनियम 1947 की धोरा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सु3(44)84-3-8म दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवाद प्रस्त या उससे संम्बधित नीचे लिखा मामलान्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबधित मामला है

क्या श्री राम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है। यदि नहीं, तो वह किस राहतक का हकदार है।

दिनांक 27 जुलाई, 1984

स॰श्रो॰बी/यमुना/ 1-84/26601:-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं प्रशासक नगर पालिका जगाधरी के श्रमिक श्री मन मोहन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य उसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्ययोगिक विवाद है :-

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं :-

इस लिये, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिस्चना स3(44)84-3-श्रम दिनांक 19 ग्रप्रैल, 1984 द्वारा उक्त ग्रिधिनियम की धारा 7के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय ग्रम्बाला का विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवादरेंसे सुसंगत ग्रथवा संबंधित मामला है।

क्या श्री मन मोहन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है। यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?